

रिश्ते जोर से नहीं प्यार मोहब्बत से पकड़े जाते हैं।

- अज्ञात

## ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य

रक्षा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत काफी पहले से महसूस की जा रही है। खासकर कारगिल युद्ध के बाद इस चर्चा में काफी तेजी आई थी। यहां तक कि मेक इन इंडिया स्कीम में भी देश में रक्षा उद्योग को विकसित करने की बात कही गई थी।

नवीन वर्मा।

‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए सरकार ने रविवार को रक्षा से जुड़ी ऐसी 101 वस्तुओं की सूची जारी की, जिनके आयात पर अगले पांच साल के लिए रोक लगी रहेगी। इसका मकसद इन वस्तुओं के देश के अंदर ही उत्पादन को बढ़ावा देना है। जिन वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने का फैसला किया गया है, उनमें गोला-बारूद से लेकर राइफल, तोप, राडार, मालवाहक विमान, हल्के लड़ाकू हेलिकॉप्टर, मिसाइल डिस्ट्रॉयर, पारंपरिक डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बी, संचार उपग्रह आदि तमाम तरह की चीजें शामिल हैं। अप्रैल 2015 से अगस्त 2020 के बीच यानी पिछले पांच साल की अवधि में इनके आयात के कुल 260 सौदे हुए हैं,

जिनका मूल्य 3.5 लाख करोड़ रुपये है। जानकार ठीक ही कह रहे हैं कि इस फैसले की बदौलत अगले छह-सात वर्षों में घरेलू इंडस्ट्री को करीब 4 लाख करोड़ रुपये के ऑर्डर मिलने वाले हैं। रक्षा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत काफी पहले से महसूस की जा रही है। खासकर कारगिल युद्ध के बाद इस चर्चा में काफी तेजी आई थी। यहां तक कि मेक इन इंडिया स्कीम में भी देश में रक्षा उद्योग को विकसित करने की बात कही गई थी। मगर इस दिशा में कोई बड़ी प्रगति अब तक नहीं दर्ज की जा सकी है, जिसका एक बड़ा कारण निश्चित और प्रतिबद्ध मांग के अभाव को माना जाता रहा है।

रक्षा वस्तुओं के उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी लगाने की जरूरत पड़ती

है, और जब तक यह गारंटी न हो कि बनाया गया माल समय से खरीद लिया जाएगा, तब तक कोई भी निवेशक इसमें हाथ नहीं डालना चाहेगा। रविवार की इस घोषणा के जरिये सरकार ने यह बाधा दूर कर दी है। निश्चित रूप से यह देश में रक्षा उद्योग के फलने-फूलने का एक बड़ा आधार साबित होगा, लेकिन अभी इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं।

देश के कुछ बड़े औद्योगिक घरानों ने विदेशी हथियार निर्माता कंपनियों के सहयोग से इस दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। ऑर्डर की गारंटी हो जाने के साथ हम निकट भविष्य में उन्हें उत्पादन इकाइयों लगाने की प्रक्रिया में जाते देख सकते हैं। कुछ मामलों में उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनियों का मुकाबला करना पड़ेगा, लेकिन अंतिम रूप से मामला

चीजों के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने और उनकी कीमत इतनी होने का रहेगा कि उन्हें घर में खरीदना बाहर से मंगाने की तुलना में पछतावे का सौदा न लगे।

यह हो जाए तो फिर एक ही सवाल बचेगा कि स्वदेशी के प्रति जताई जा रही प्रतिबद्धता क्या सीमा पर संकट के वक्त भी कायम रहेगी। हमारी सेना हर चुनौती से निपटने में सक्षम है और हम किसी भी स्थिति का मुकाबला करने को तैयार हैं, ऐसी तमाम घोषणाओं के बावजूद अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही सीमा पर तनाव बढ़ता है, विदेशों से रक्षा खरीद अचानक बढ़ जाती है और देखते-देखते दसियों हजार करोड़ के सौदे हो जाते हैं। आत्मनिर्भरता की परख दरअसल ऐसे क्षणों में ही होती है।

## अंतहीन प्रक्रिया

अशोक वोहरा।

इस बात को

आप तभी देख

सकेंगे जब आप

हर किसी की

पहचान इस तरह

से करना बंद

कर दें, प्यह

जीवन है, यह

जीवन नहीं है,

इसमें प्राण हैं,

इसमें प्राण नहीं हैं,

यह पुरुष है, यह

स्त्री है। हर चीज को बस वैसी ही

देखिए जैसी वह है। तो, यही सब

कुछ है जैसा कुछ भी नहीं होता।

यह तल्लीन हो जाने की एक

अंतहीन प्रक्रिया है। मान लीजिये कि

एक ऐसी स्थिति हो जब आप कहें,

शयही सब कुछ है, तो फिर उसके

बाद आप क्या करेंगे?

जब आप ब्रह्मांडीय जीवन जीने

लगते हैं, तो जीवन अलग हो जाता

है। क्या ये सुन्दर होता है ? नहीं !

क्या ये गन्दा होता है ? नहीं ! तो

फिर ये कैसा है ? जीवन की तरह,

जैसे इसे होना चाहिये, इस तरह या

उस तरह नहीं। हर चीज वैसी ही

है, जैसी उसे होना चाहिये।

धर्म-दर्शन



## संपादकीय

### नौरोजी की राह

अन्य प्रवासी आबादियों के कम राजनीतिक दखल की एक बड़ी वजह शायद यह है कि लोकतंत्र उनके सामाजिक लोकाचार का हिस्सा उस तरह नहीं बन पाया, जैसा संसार के सबसे पुराने लोकतंत्र से लंबे राजनीतिक संघर्ष के क्रम में भारत के साथ हुआ। हमारा लोकतंत्र ऊपरी तौर पर चाहे जितना भी अपंग दिखे लेकिन एक आम भारतीय को दुनिया के किसी अंधेरे कोने में फेंक दिया जाए तो भी अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को छोड़ने के लिए वह आसानी से राजी नहीं होगा। इस सहज वृत्ति के आगे क्षमता का सवाल आता है, जो एक पराये समाज में प्रायः वकील या व्यापारी बनकर ही हासिल हो पाती है। बिजनेस से पॉलिटिक्स का रास्ता सबसे पहले दादाभाई नौरोजी ने बनाया था, उन्नीसवीं सदी में ब्रिटिश सांसद बनकर। अभी ब्रिटेन के वित्तमंत्री और गृहमंत्री चार पीढ़ी पहले अफ्रीका में बसकर उजड़े भारतीयों के वंशज हैं और वकालत तथा व्यापार से ही राजनीति में आए हैं। चीनी मूल वालों का ऐसा, बल्कि इससे ज्यादा राजनीतिक दखल सिर्फ सिंगापुर में है, जिसे लोकतंत्र जरा ठिठक कर ही कहा जा सकता है। थाईलैंड में उनकी आबादी वहां की कुल जनसंख्या का तकरीबन 14 प्रतिशत है, मगर राजनीतिक प्रतिनिधित्व शून्य है। अन्य देशों में भी अच्छी-खासी आर्थिक स्थिति के बावजूद वे इसके लिए कोई प्रयास नहीं करते। ध्यान रहे, सबसे ज्यादा भारतीय 1995 से शुरू हुए ग्लोबलाइजेशन के बाद विदेश पहुंचे हैं, जहां उनका प्रभाव जबर्दस्त है। लेकिन वहां सीधे राजनीतिक दखल की स्थिति में शायद उनके बच्चे ही पहुंच पाएं।

ट्रंप और उप राष्ट्रपति माइकल पेंस, जबकि विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उन्हें चुनौती दे रहे हैं राष्ट्रपति पद पर पूर्व उप राष्ट्रपति जोसफ बाइडन और उप राष्ट्रपति पद के लिए उनकी पसंद कमला हैरिस।

## घुली-मिली पहचान

चंद्रभूषण ।।

अमेरिकी आम चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। कोविड-19 की वजह से कुछ प्राइमरीज की तिथियों में फेरबदल के बावजूद आम चुनाव की तारीख में बदलाव की कोई संभावना नहीं है और आगामी 3 नवंबर को ये संपन्न हो जाएंगे। चुनावी जंग की अगुआई कर रहे हैं सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और उप राष्ट्रपति माइकल पेंस, जबकि विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उन्हें चुनौती दे रहे हैं राष्ट्रपति पद पर पूर्व उप राष्ट्रपति जोसफ बाइडन और उप राष्ट्रपति पद के लिए उनकी पसंद कमला हैरिस। इन चार में से तीन उम्मीदवारों की सारी कहानियां अमेरिकी मतदाता कई-कई बार सुन चुके हैं, लेकिन कमला हैरिस की कहानियां उनके लिए नई हैं। यूं कहें कि जितने किस्से बराक ओबामा को लेकर 2008 के चुनाव में उन्हें सुनने को मिले थे, उससे कुछ ज्यादा ही इस बार कमला हैरिस को लेकर सुनने को मिलेंगे।

कमला की मां श्यामला गोपालन विदेश उप-सचिव पीवी गोपालन की बेटी थीं और दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज से बी.एससी. (बायो) करके बर्कले (कैलिफोर्निया) में आगे की पढ़ाई करने गई थीं। एंडोक्राइनॉलजी में उनका



दंग का काम है और ब्रेस्ट कैंसर में सेक्स हार्मोन्स की भूमिका रेखांकित करके उन्होंने इस क्षेत्र में शोध की दिशा बदल दी थी। ज्यादा बड़ी बात यह कि भारत में वैज्ञानिक दायरों के घरघुसू दक्षिणपंथी रुझान के विपरीत 1962-63 के उस बेचौन दौर में वे अमेरिकी मानवाधिकार आंदोलन के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी थीं।

इस आंदोलन में ही उनकी मुलाकात जमैका से आए, ब्रिटेन में पढ़े अर्थशास्त्री डॉनल्ड हैरिस से हुई, जिन्हें कीन्स की राज्य समर्थित पूंजीवाद वाली थीसिस में कई प्रो-पीपल बदलावों के लिए जाना जाता है। 1963 में दोनों की शादी हुई। हिंदू रिवाज के मुताबिक माला पहनकर और बैप्टिस्ट प्रथा के अनुसार कांच का गिलास तोड़कर। फिर कमला और माया, दो बेटियां हुईं, जिनके नाम को लेकर शुरू हुई पति-पत्नी की अनबन 1971 में तलाक के साथ खत्म हुई।

एक ठेठ राजनेता की तरह कमला हैरिस के

साथ कई सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक किस्से भी जुड़े हैं लेकिन अपनी पहचान अगर वे मॉडर्न अमेरिकन के अलावा हिंदू और बैप्टिस्ट, भारतीय और जमैकन सब एक साथ बताती हैं तो कुछ गलत नहीं कहतीं। अमेरिका में पुरानी पहचानें ज्यादा नहीं चलतीं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पुराने रिश्ते टूटने पर वहां लोग नए रिश्ते बनाने में ज्यादा देर नहीं लगाते। लेकिन जिस उमर में अमेरिकी खुद को जवान होते देखते हैं, उसी उमर में तलाक हो जाने के बावजूद कमला हैरिस की मां और पिता, दोनों ने दूसरी शादी नहीं की और अपने बच्चों से जुड़े रहे।

कमला को अपने पिता के साथ जमैका जाने का मौका पता नहीं कितना मिला, पर चैनै में अपने नाना के साथ समुद्र तट पर बिताए गए वक्त का जिज्ञास वे बड़े चाव से करती हैं। एक वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री की बेटी का कानून पढ़ना भी एक फैसला रहा होगा, जो कमला ले पाईं तो इसकी वजह बचपन में अपने साथ हुए रंगभेद के प्रतिकार के लिए समाज में ज्यादा दखल देने की उनकी इच्छा ही थी।

यहां पहुंचकर हमारा सामना इस सवाल से होता है कि भारतीय प्रवासियों की तादाद चीनियों की लगभग आधी और ज्यादातर देशों में कई और देशों से आए प्रवासियों से काफी कम होने के बावजूद उनका राजनीतिक प्रभाव औरों से ज्यादा क्यों है।

सूटोपु नवताल-5443		****	
8		1	5
2		1	8
3	4	6	9
5		9	
9	2 3 4		7
	1		8
4	7 6	5	1
	6 7		4
5 3		2	

## अपना ब्लॉग

राजनीतिक भूमिकाओं में रहना स्वाभाविक

**मोहन।** ब्रिटेन के वित्तमंत्री और गृहमंत्री, दोनों अभी भारतीय मूल के हैं। कैबिनेट बैठती है तो तीन कुर्सियों पर देसी नामों की चिपियां लगी होती हैं—ऋषि सुनक, प्रीति पटेल और आलोक शर्मा। कनाडा में यह संख्या चार हो जाती है—अनीता आनंद, नवदीप बेंस, बरदीश चग्गर और हरजीत सज्जन। जहां भारतीय मूल के लोग बीस फीसदी से ज्यादा हैं, मॉरिशस, फिजी और कई कैरिबियाई मुल्क, वहां तो उनका बड़ी राजनीतिक भूमिकाओं में रहना स्वाभाविक है, सो उन्हें छोड़ते हैं। मसलन, मॉरिशस में हाल-हाल तक भारतीय या तो खेतों में मजदूरी करते थे या ड्राइवर-खलासी जैसे छोटे-मोटे काम संभालते थे, जबकि गली-मोहल्ले की दुकानदारी पूरी तरह चीनियों के हाथ में थी। लेकिन आजादी मिलने और लोकतंत्र आने के साथ भारतीय आबादी ने विधायक-मंत्री बनने की कोशिशें तेज कीं जबकि तीन फीसदी चीनी आबादी आज भी दुकानदारी या नौकरी-चाकरी तक ही सीमित है।

मौसम विभाग से फोन पर पूछो  
चड़्डी-बनियान गीली होने वाली  
बारिश कब होगी...

